(b) if so, what steps are being taken for efficient collection and disposal or recycling of garbage to avoid diseases breeding as a consequence?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken for efficient collection and disposal of garbage:

(i) The garbage is collected in 495 dalaos and 2382 dustbins and in addition the garbage collected from open collection sites is removed daily to the land fill sites. The average collection of garbage is about 4,000 M.T|day and the same is being dumped at the land fill sites.

(ii) The garbage is levelled and insecticides such as BHC 5 percent and 50 per cent is used to control foul smell, in addition baygon Bait solution is spread over the garbage to kill larvas and adult flies and lastly 30 cm depth of sweat earth is put for carrying out horticulture work|woodland.

(iii) A survey of the Urban Municipal Waste is to be carried out by MCD to find the quantum of recylable waste material present in the garbage so that it is put to recycle end reuse and not disposed on land.

कुल्लू में राष्ट्रीय उद्यान

1710. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) कुल्लू जिले (हिमाचल प्रदेश) में प्रस्तावित विशाल राष्ट्रीय उद्यान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि वर्षवार उपलब्ध कराई गई है और यह धनराशि जिन-जिन शीर्षों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है, उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त उद्यान के लिये अधिग्रहीत की गई अथवा अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के लिये भू-स्वामियों अर्थात् स्थानीय लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है ,

(ग) यदि हां, तो कब ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उन स्थानीय लोगों को भी मुआवजा दिया गया है, जो उक्त क्षेत्र से जड़ी-बूटी एकत्र किया करते थे और जिन्हें वहां पर अपनी भेड़-बकरियां चराने का अधिकार प्राप्त था ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, कुल्लू, (हिमाचल प्रदेश) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का शीर्ष सहित वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन (लाखों रुपयों में)	स्कीम	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष
1986–87	3,86,000	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	3601	डी 2(5) (1)
1987–88	14,14,000			
1988–89	14,38,000			
1989–90	18,53,000			
1990–91	21,04,000			
1991–92	25,88,000			
1992–93	18,72,000			

केन्द्र सरकार द्वारा 1984-85 से 1992-93 तक 1,45,96,595/- रुपए की सहायता दी गई है ।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के तहत कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान बनाने के अपने इरादे के बारे में एक अधिसूचना जारी की है तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम की धारा 19 की शर्तों के अनुसार कलैक्टर के रूप में उद्यान की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि पर लोगों के अधिकारों की जांच कर रहे हैं । प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान कलैक्टर के अंतिम निर्णय एवं अधिकारों के निर्धारण पर निर्भर करेगा ।

(ङ) उन सभी व्यक्तियों, जिनके अधिकार प्रभावित हुए हैं, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत मुआवजा दिया जायगा ।

विभिन्न नदियों की सफाई हेतु योजना तैयार किया जाना

1711. **श्री राम नरेश यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न नदियों की सफाई हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि इन्हें प्रदूषण-मुक्त किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कानून बनाने अथवा जल-प्रदूषण को कम से कम करने के लिये दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषण निवारण के लिये एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का प्रतिपादन किया जा रहा है । इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसमें अन्य देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जाना शामिल है ?

Forest land for plantations

1712. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that paper industry has sought cheap forest land for plantations;

(b) if so, to what extent the proposal has been appreciated by Government;

(c) whether it is a fact that paper industry has been given enormous subsidy in terms of state-supplied raw material; and

(d) what steps are taken by Government to ensure ecological standards in view of growing demands of the paper industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) National Forest Policy, 1988 states that that the practice of supply of forest produce to industry at concessional price should cease.

(d) To ensure ecological standards in view of growing demands of the paper industry, steps taken by the government are as follows:—

(i) Encouraging manufacture of paper from agricultural wastes.